



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2022/भाग(10)/1175

दिनांक :: 27 मई, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 18 मई, 2022 को सांय 4.00 बजे श्री हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए गत बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण कि बैठक दिनांक 18.04.2022 में आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 एवं वास्तविक आय-व्यय वर्ष 2021-22 पारित करवाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने बाबत।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण कि बैठक दिनांक 06.05.2022 में आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 एवं वास्तविक आय-व्यय वर्ष 2021-22 पारित करवाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने बाबत	जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आय व्यय के अनुमोदन कि अनुशंषा कि जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आय व्यय के अंक जिनका विस्तृत विवरण संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत है, एतद् द्वारा आयुक्त महोदय के अवलोकन एवं तत्पश्चात उनके द्वारा सुझाये गये उपान्तरणों के समावेश पश्चात इसको प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु रखने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत है। प्राप्तियों-एवं व्यय का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :-

(रु लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	आय व्ययक के अनुमान 2021-22	वास्तविक आय व्यय 2021-22	आय व्ययक अनुमान 2022-23
1	कुल प्राप्तियाँ	88050.00	28537.04	106410.00
2	कुल व्यय	88050.00	22241.08	106410.00

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में निदेशक-वित्त द्वारा प्रस्तुत आय व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 एवं वास्तविक आय व्यय वर्ष 2021-22 जो कि इस कार्यवाही विवरण का भाग परिशिष्ट-2 है, का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 15150/2021 भंवर सिंह बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल को विशेष फीस के रूप में 5-5 लाख रुपये के भुगतान बाबत प्रस्ताव।

डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 15150/2021 भंवर सिंह बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रुपये 5,00,000/- एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल द्वारा राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रुपये 5,00,000/- को स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव संख्या 50 के रूप में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 में प्रस्ताव संख्या 50 का अनुमोदन करते हुए इसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की अभिशंका की।

अतः कार्यकारी समिति की अभिशंका के अनुसार उपरोक्त विधिक फीस के भुगतान के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार विधिक फीस के भुगतान करने के कार्यकारी समिति के निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 13782/2021 रोशन व्यास बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल को विशेष फीस के रूप में 5-5 लाख रुपये के भुगतान बाबत प्रस्ताव।

डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 13782/2021 रोशन व्यास बनाम सरकार व अन्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह द्वारा प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रुपये 5,00,000/- एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल द्वारा राज्य एवं नगरीय विकास विभाग की ओर से पैरवी हेतु प्रस्तुत फीस बिल राशि रुपये 5,00,000/- को स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव संख्या 51 के रूप में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।



कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 में प्रस्ताव संख्या 51 का अनुमोदन करते हुए इसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की अभिशंषा की।

अतः कार्यकारी समिति की अभिशंषा के अनुसार उपरोक्त विधिक फीस के भुगतान के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार विधिक फीस के भुगतान करने के कार्यकारी समिति के निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के पारित होने की प्रत्याशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को स्वीकृति से जारी अत्यावश्यक विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्राधिकरण बैठक में करवाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

क्रं. सं.	प्रमारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के पारित होने की प्रत्याशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को स्वीकृति से जारी अत्यावश्यक विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्राधिकरण बैठक में करवाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

क्र.सं. -जोब सं	कार्य का नाम	बजट शीर्षक	(लाखों में)	
			जोन	राशि
1	विवेक विहार में 100 के.वी.ए ट्रांसफार्मर लगाने हेतु।	5002-4-3-(3)	दक्षिण	16.47
2	नगर निगम उत्तर के क्षेत्राधिकार में पंच मरम्मत कार्य।	5005-3-0-(1)	उत्तर	147.00
3	गौशाला मैदान में हाइड्रोथरेपी पुल में सफाई हेतु क्लीनर मय मोटर उपलब्ध करवाने का कार्य	5005-01-000-(06)	पूर्व	0.40
4	गणेश मंदिर उद्यान में चैनलिंग फैनसिंग व झुले लगाने का कार्य	5005-1-000-(06)	पूर्व	1.90
5	नगर निगम दक्षिण के क्षेत्राधिकार में पंच मरम्मत कार्य	5005-4-000-(01)	दक्षिण	30.00
6	टेबल टेनिस कोर्ट की मरम्मत का कार्य (गौशाला मैदान) (Deposit work)	5007-01-000-(22)	पूर्व	5.00
7	स्केटिंग मैदान की मरम्मत का कार्य (गौशाला मैदान) (Deposit work)	5007-01-000-(22)	पूर्व	3.70
8	बेडमिन्टन बुडन कोर्ट की मरम्मत का कार्य (गौशाला मैदान) (Deposit work)	5007-01-000-(22)	पूर्व	5.00
9	टेनिस कोर्ट की मरम्मत का कार्य (गौशाला	5007-01-000-(22)	पूर्व	9.00

	मैदान) (Deposit work)			
10	क्रिकेट पिच की नेट प्रेक्टिस की जाली की मरम्मत (गौशाला मैदान)	5007-01-000-(22)	पूर्व	2.00
11	JDA Computerization work payment	5001-07-20-(0)	मुख्यालय	66.00
12	अरबन हाट बाजार पाली रोड़ के नवीनीकरण की DPR बनाने का कार्य	5008-1-0-(0)	पूर्व	8.00
13	गौशाला मैदान में सिविल मरम्मत का कार्य	5005-01-00-(06)	पूर्व	1.99
14	सम्राट अशोक उद्यान परिसर में स्थित विभिन्न भवनों की मरम्मत रख रखाव का कार्य (वार्षिक अनु.)	5005-02-000-(09)	पश्चिम	17.50
15	सम्राट अशोक उद्यान के सम्पूर्ण परिसर ऑपन एयर थियेटर का सम्पूर्ण परिसर की साफ-सफाई का कार्य	5005-02-000-(09)	पश्चिम	10.92
16	Development of Garden (Green Space) using Junk material (Inspired the rock garden, Chandigarh) at surpura Dam, Jodhpur (Phase-2nd)	5003-05-000-(00)	उत्तर	1397.97

उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली में अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा बजट की प्रत्याशा में अनुमोदित की गई है। उक्त कार्यों की राशि का प्राधिकरण के बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में समावेश कर लिया गया है। बजट स्वीकृति की प्रत्याशा की गई A&F की स्वीकृति प्राधिकरण बैठक में किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में नवीन राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में नवीन राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में नवीन राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

आयुक्त महोदय जोविप्रा एवं जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर-बी में संस्थागत प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

जो

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भवन विनिमय 2020 अनुसार शैक्षणिक संस्थान को संस्थागत भवन की श्रेणी में दर्शाया गया है। विवेक विहार हेतु पूर्व में बैठक दिनांक 10.04.2019 में ले-आउट प्लान समिति के निर्णयानुसार प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 में उल्लेख अनुसार सुविधा क्षेत्रों हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवश्यकतानुसार सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रयोजनार्थ उपयोग अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर-बी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा महाविद्यालय प्रयोजनार्थ 10,000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण की अवाप्तसुदा भूमि में विकसित एवं अधिसूचित कॉलोनी विवेक विहार योजना के सेक्टर-बी में स्थित है। उक्त भूमि की वर्तमान रिजर्व प्राईज 13,000/- रु. प्रतिवर्गमीटर है इसके आधार पर उक्त भूमि की कीमत $13,000 \times 10,000 = 13,00,00,000/-$ (13 करोड़) रुपये होते हैं। लेकिन विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

तत्पश्चात उक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के प्रस्ताव संख्या 57 के अनुसार कार्यकारी समिति की अभिशंभा के साथ प्रकरण आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1337 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाइट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर-बी में संस्थानिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से राजकीय महाविद्यालय प्रयोजनार्थ 10,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर-बी में संस्थानिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से राजकीय महाविद्यालय प्रयोजनार्थ 10,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ का जोन चिन्हिकरण बाबत।

प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंभा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ का जोन चिन्हिकरण बाबत।

प्राधिकरण में आईसीडी (इनलेण्ड कन्टेनर डिपो) के विस्तारिकरण हेतु सालावास रेल्वे स्टेशन के समीप राजसीको द्वारा भूमि आवंटन की मांग की गयी है। साथ ही उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नवीन भण्डारगृह निर्माण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गयी है। उक्त के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर उपायुक्त दक्षिण द्वारा राजकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर खसरा संख्या 218 राजस्व ग्राम तनावडा में आवंटन हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। खसरा संख्या 218 के पास ही प्राधिकरण की भूमि खसरा संख्या 183 व 189 में भी उपलब्ध है, राजसीको व केन्द्रीय भण्डार निगम के प्रस्तावों के दृष्टिगत इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ योजना बनाई जा सकती है। वर्तमान में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान में उक्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय डी.सी.आर अनुसार अज्वलनशील गोदाम को 24 मीटर (80 फीट) व अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार सामान्य वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग को मास्टर प्लान के प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किया गया है व समस्त नगर निकाय द्वारा उक्तानुसार प्रभावी मास्टर प्लान में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन का चिन्हिकरण किया जाना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में जोन से प्राप्त राजकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर खसरा संख्या 218, 189, 183 का भाग राजस्व ग्राम तनावडा में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन चिन्हिकरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसर है।

- पूर्व दिशा :- नवीन प्रस्तावित 24 मीटर सडक एवं खसरा संख्या 219 (राजस्व ग्राम तनावडा)
पश्चिम :- नवीन प्रस्तावित 24 मीटर सडक एवं खसरा संख्या 188 व 183 का भाग
(राजस्व ग्राम तनावडा)
उत्तर दिशा :- जोजरी नदी के साथ प्रस्तावित 18 मीटर सडक एवं भाकरासनी गांव से
सालावास जाने वाली 30 मीटर सडक
दक्षिण दिशा :- प्रस्तावित 24 मीटर सडक एवं खसरा संख्या 190, 191, 192, 193 व 217
(राजस्व ग्राम तनावडा)
कुल क्षेत्रफल (गूगल मानचित्र अनुसार) 24 है०

प्रस्तावित जोन के समीपीय प्रस्तावित जोन की बाहरी सीमाओं पर सुगम यातायात व आवासीय क्षेत्र से बफर हेतु 24 मीटर सडक प्रस्तावित की गयी है। निजी भूमि धारकों से भी वेयर हाउस/गोदाम के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाकर व उचित प्रस्तावों का समायोजन जोन में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त जोन के उत्तर दिशा में भाकरासनी सालावास 30 मीटर सडक व पश्चिम दिशा में मास्टर प्लान की तनावडा फांटा जाने वाली 30 मीटर सडक पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगवायी जानी प्रस्तावित है।

जोन चिन्हिकरण हेतु प्रस्ताव पर आमजन से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना भी प्रस्तावित है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 को एजेण्डा संख्या 38 पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।



प्रस्ताव संख्या 8 :: नवीन व्यवसायिक योजना खसरा संख्या 706 व 707 ग्राम चौखा।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नवीन व्यवसायिक योजना खसरा संख्या 706 व 707 ग्राम चौखा योजना की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु अभिशंषा की जाती है।

ले-आउट प्लान दिनांक 26.11.2021 के एजेण्डा सं. 36 अनुसार ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया जिसमें योजना का नाम विश्वकर्मा मार्केट नाम से किया गया। इसी की बैठक दिनांक 15.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 24 के निर्णयानुसार योजना की आरक्षित दर 22,000/- रु प्रति वर्गमीटर अनुमोदित की गई है। योजना में विभिन्न माप के कुल 164 भूखण्ड है।

ग्राम चौखा के खसरा संख्या 706 व 707 में कुल क्षेत्रफल 38 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर भवन निर्माण सामग्री मार्केट नवीन योजना लांच की जानी है जिसमें भूखण्डों का आवंटन निलामी द्वारा किया जाना है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियां जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा (7) (2) {iv} Preparation of projects and schemes; के तहत आरक्षित दर 22000/- रु प्रति वर्गमीटर अनुमोदन किया जाता है एवं उक्त अनुमोदन पश्चात्तर्वर्ती section {16} {b} formation and sanction of the projects and schemes for the development of the jodhpur region or any part thereof. के तहत प्राधिकरण की शक्तियों के अनुरूप योजना के भूखण्डों का आवंटन निलामी द्वारा विक्रय किया जाने एवं योजना की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: संगीत कलाकारों को रहवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु ग्राम चौखा खसरा संख्या 28 नवीन योजना।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	संगीत कलाकारों को रहवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु ग्राम चौखा खसरा संख्या 28 नवीन योजना की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु अभिशंषा की जाती है।

ले-आउट प्लान दिनांक 26.11.2021 के एजेण्डा सं. 39 अनुसार के निर्णयानुसार ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया।

जुए

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 24 के निर्णयानुसार योजना की आरक्षित दर 9000/- रु प्रति वर्गमीटर निर्धारित का अनुमोदन किया गया।

ले-आउट प्लान अनुमोदन अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के कुल भूखण्ड 1818 एवं इन्फोरमल मार्केट 10×10= 128 भूखण्ड है। परम्परागत कलाकार जातियों- मिरासी, लंगा, कालबेलिया, ढाढी, रावल, भोपा, मांगनियार, गाडिया लौहार इत्यादि को भूखण्ड का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाना है।

ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में कुल क्षेत्रफल 323862.72 वर्गमीटर भूमि पर परम्परागत कलाकार जातियों- मिरासी, लंगा, कालबेलिया, ढाढी, रावल, भोपा, मांगनियार, गाडिया लौहार इत्यादि को नई आवासीय योजना लांच की जानी है जिसमें भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाना है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियां जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा (7) (2) {iv} Preparation of projects and schemes; के तहत आरक्षित दर 9000/- रु प्रति वर्गमीटर अनुमोदन किया जाता है एवं उक्त अनुमोदन पश्चात् वर्ती section {16} {b} formation and sanction of the projects and schemes for the development of the jodhpur region or any part thereof. के तहत प्राधिकरण की शक्तियों के अनुरूप योजना के भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाने एवं कॉर्नर भूखण्डों को निलामी द्वारा विक्रय किया जाने तथा योजना का नामकरण एवं योजना की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोविप्रा में वर्तमान में प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन SOP को संशोधित कर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन बाबत।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोविप्रा में वर्तमान में प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन SOP को संशोधित कर प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में वर्तमान में विकास कार्य, सामग्री एवं सर्विस हेतु प्रचलित शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) दिनांक 1 मई 2017 को लागू की गई थी इसके पश्चात् वित्त विभाग द्वारा संशोधन किये गये हैं। उन संशोधन का समावेश एवं व्यावहारिकता की दृष्टि से संशोधन की आवश्यकता है अतः वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन (SOP) में आवश्यक संशोधन जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.21 के प्रस्ताव संख्या -13 द्वारा अनुमोदित है। कार्यकारी समिति का निर्णय निम्नानुसार है :-

“ बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक वित्त ने अवगत कराया कि प्रचलित (SOP) शक्तियों के प्रत्यायोजन में उपापन समिति में गठन में परिवर्तन प्रस्तावित कर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को अनुशंषा कमेटी से पृथक किया गया है। साथ ही कार्यकारी समिति की बैठक 06.02.19 एवं 07.03.19 में SOP के Item No - 26,27,29 (iii), 19 किये गये संशोधनों को प्रचलित SOP में समावेश किया

जे.ए.

गया। Goods & Services के Item की शक्तियों में A&F स्वीकृति, Bid स्वीकृति एवं Bid evaluation committee के गठन का प्रावधान किया गया है।”

“जोधपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद स्वीकृत होने पर संबंधित आइटमों में ACE को शक्तियों का भी समावेश किया गया है। Consultancy Services की शक्तियों में परिवर्तन, completion certificate जारी करना, Rate analysis एवं विशिष्टियों का अनुमोदन करना, बजट प्रावधान का पुनर्नियोजन की शक्तियों, Single source Procurement Committee, spot purchase Committee का भी समावेश किया गया। जो आइटम work से संबंधित नहीं उन्हें Goods & Services शीर्षक में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।”

प्राधिकरण बैठक दिनांक 13.04.22 के प्रस्ताव संख्या 04 में हुए विचार विमर्श के अनुसार SOP का पुनः परीक्षण EC के माध्यम पुनः प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किये गये थे। इसकी पालना में परीक्षण उपरान्त SOP कार्यकारी समिति की बैठक 26.04.2022 के प्रस्ताव संख्या 58 द्वारा उपरोक्त संशोधन को अनुमोदित कर कार्यकारी समिति की अनुशंसा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचरार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। अतः इसकी पालना में S.O.P. का प्राधिकरण बैठक दिनांक 06.05.2022 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। स्वीकृति उपरान्त S.O.P. का राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाने का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

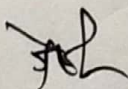
Delegation of Powers to the Officers of Jodhpur Development Authority, Jodhpur

SOP Effective from 1st day of May 2017 (Revised on -----)

Part - I (Works)

General Note:-

1. Estimates should be framed at prevailing BSR.
2. Rate analysis of works shall be prepared by concerned Ex En. and counter signed by Director Eng. Before opening of price bid of the tender.
3. All powers, which are not specified in the schedule below, involving financial implication up to Rs. 500.00 Lacs, shall vest with JDC.
4. For delegation of powers which are not covered in this schedule of powers shall be *mutatis mutandis* applied as per PWF & AR and RTPPR 2013.
5. Bid amount means the amount offered by the Bid/contractor intended to be sanctioned.
6. Estimated amount means sanctioned estimated amount of item of BOQ schedule of work concerned.
7. Bid premium means percentage rate above/below quoted by the tenderer over BOQ Schedule amount.
8. A financial power of an authority, given under those rules, shall automatically vest in all higher authorities of that authority.
9. The financial power, not specifically delegated to any authority, shall vest with authority subject to RTPP Act & Rules.
10. No Administrative/Financial sanction shall be issued without appropriate budget provision. All sanctions shall be strictly restricted unto the limits of available Budget.
11. Wherever any specific power for a purpose has been given to an authority under this delegation, then it shall prevail over the general powers (if any) for that purpose.
12. The powers shall be subject to the budget provision in general and to the specific budget provisions, wherever mentioned in these delegations.



13. The powers contained in these delegations shall be subject to the rules and other provisions contained in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012; Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013. Time to Time Amendment in RTPP act & rule will be applicable as it is.
14. Splitting of works for the purpose of keeping bids in its own competence by any officer is an irregularity. Therefore, splitting of bids should not be resorted to. If however, in genuine cases, it becomes necessary in the interest of work to split up, it should be done only after obtaining prior permission of the authority competent to sanction the bid of work without split up. The competent authority shall, while according permission mention the reasons for splitting of works.
15. The powers shall exercised only after comments/examination by the senior most Accounts Personnel (Director Finance/ Chief Accounts Officer/ Senior Accounts Office/ Accounts Officer/ Assistant Accounts Officer) Posted in the Office. While conveying sanction, the reference of comments/examination by Accounts Personnel shall be mentioned. However, if the sanctioning authority differs with the advice of Accounts Personnel, the case must be submitted to next higher authority.
16. Wherever the words "bid amount" have been used in these powers, it means the amount offered by the bidder/ contractor which is intended to be sanctioned.
17. Wherever the words "estimated amount" are appearing, it means sanctioned estimated amount of items of G-Schedule or BOQ of the work concerned as the case may be.
18. "Bid premium" means percentage rate above/below quoted by the contractor over department rates or if worked out in item rates, the percentage of bid amount over sanctioned estimated amount for deciding competence to sanction bid.
19. Ensure that approved drawing & designs etc. are ready before NIB and land has been made over before sanction of Bid. Other actions required office level has been completed before sanction.
20. JDA shall prepare a procurement plan as per provision of Rule 7 of RTPP Rules, 2013.
21. Authority means the Jodhpur Development Authority constituted under section 3 of the Jodhpur Development Authority Act 2009.
22. As on today post of A.C.E. does not exist in cadre strength. However the same has been included in SOP with a view to its creation in near future .

ABBREVIATION	
EC : Executive Committee	GF & AR : General Financial & Accounts Rules
JDC : Jodhpur Development Commissioner	NIB : Notice Inviting Bid
DF : Director Finance	PPP : Public Private Partnership
DE : Director Engineering	PWF & AR : Public Works Financial & Accounts Rules
AE : Assistant Engineer	RTPP : Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013
AMC : Annual Maintenance Contract	SE : Superintending Engineer
AS : Administrative Sanction	T&P : Tools & Plant
BOT : Build- Operate & Transfer	TS : Technical Sanction
BSR : Basic Schedule of Rates	FS : Financial Sanction
CAO : Chief Accounts Officer	PC : Procurement Committee
EE : Executive Engineer	ACE : Additional Chief Engineer
ACE: Additional Chief Engineer	

ST

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS				
1	Administrative & Financial approval to execute a Project/Scheme/Works in whole or part including repairs and maintenance.	EC	FULL POWERS	Unless restricted by State Govt
		JDC	Up to Rs. 5.00 Crore	On recommendation Public works committee If Amt. is 50 lac & above
2	Revised Administrative & Financial approval to execute a Project/Scheme/ Works in whole or part including repairs and maintenance.	E.C. (Incl usive of Revised A&F s)	Above Rs. 5.00 Crore Up to 50% of original value of the Contract	Note= (i) Revised estimate must be sanctioned by competent authority before the proposal for revised A&F (ii) As per RTPP Rule-73(3)(iii)
		JDC (Incl usive of Revised A&F s)	Up to Rs. 5.00 Crore up to 50% of original value of the Contract	
3	Splitting of A & F Sanctions.	DE	Full power	(With Recommended of Bid Sanction Authority of work without split up) (see general note 14)
4	To permit undertaking contribution/ deposit works and to accept contribution/ deposit in respect of them.	EC	Full Power	These powers shall be exercised subject to following conditions: - Note: - 1. Deposits may be accepted in lump sum or in installments on prescribed dates as mutually agreed after ensuring that full amount is provided for in the budget of the concerned organisation and installments would be paid on specified dates. 2. Deposit works involving share of JDA will be agreed/ sanctioned only with the concurrence of
		JDC	Up to Rs. 1000.00 Lacs	
		DE	Up to Rs. 300.00 Lacs	
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
EE	Up to Rs. 30.00 Lacs			

JCB

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
				<p>EC. Revised cost will also be borne in the same proportion as decided by EC.</p> <p>3. Expenditure will be charged against and limited to the deposit received only, in no case it should exceed the deposit.</p> <p>4. Percentage charges, as approved from time to time, shall be levied as decided in byelaws/administrative orders.</p>

TECHNICAL SANCTIONS

5	To accord technical sanction to detailed original/revised or supplementary estimated based on A&F sanction already available for original work, deposit works contribution works subject to the condition that revised A&F shall be sought in Advance, If the revised as supplementing estimate exceed the original A&F sanction by more than 10%	DE	Full Power	<p>These powers shall be exercised subject to following conditions only: -</p> <p>Note: -</p> <p>1. There is provision in the administrative approval to cover the particular type of work and sanction of the detailed estimates does not result in excess of more than 10% over the provision under the particular sub-head of the administratively approved project estimate under which the estimate is sanctioned but it shall not exceed the administrative approval of the project as a whole.</p> <p>2. Revised estimate involving excess of more than 10% over original sanctioned estimate shall be submitted to the next higher authority for technical sanction after obtaining revised AS/FS from Competent</p>
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 50.00 Lacs	

SKL

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>Authority. In case of CE is next higher authority will be CE himself (CE means Chief Engineer)</p> <p>3. If the cost of the work, according to the revised estimates, exceeds the limits of the powers to accord technical sanction, the revised estimate should be submitted to the next higher authority. In CE next higher authority will be CE himself.</p> <p>4. Revised Administrative & Financial approval is obtained if revised cost is more than 10% of original cost. PWF&AR-286&287</p> <p>5. For supplementary estimate, the authority who sanctioned original estimate will be competent provided original plus supplementary is in his competence.</p> <p>6. No officer is competent to pass any excess over a revised estimate sanctioned by an authority higher than himself.</p> <p>7. For subsequent revision of estimate also, the amount of estimates shall form basis for revision.</p> <p>8. Rates of Non BSR items shall however be approved by the DE only.</p>
6	To accord administrative and technical approval/Terms of Reference's approval of a consultant and to approve bids for conducting of	EC	Full Power up to 2% of the project cost.	<p>Note: -</p> <p>1. A certificate is to be recorded by the Approving Authority that the departmental organisation existing for</p>
		JDC	Up to Rs. 50.00 Lacs or 2% of the project cost	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	detailed surveys and investigation, preparation of designs and drawings, project formulation and preparation and other studies, appointing consultant, hiring of consultancy services etc., other than by department agency e.g. private consultancy services.		whichever is less.	the work is either fully occupied or is not well equipped for the job. 2. Procurement is made as per & RTPP Act/Rules. (PWF&AR-306A) 3. Retired personnel will not be eligible for such assignments for two years after retirement, except with specific Government sanction. 4. There should be specific budget provision for this purpose.
		DE	Up to Rs. 15.00 Lacs or 2% of the project cost whichever is less.	
7	To accept bids for works on Build, operate and Transfer (BOT) basis, PPP Projects including acceptance of bids for consultancy of these projects.	EC	Full Power	Guidelines set by state government should be followed
8	In emergent conditions like flood relief and other natural calamities, the subject matter of procurement may be procured upto the ceiling rates fixed by district level committee. Constituted under RTPPR-17(3)	EC	Up to Rs. 100.00 Lacs	Note 1. Procurement shall be done as per RTPP Act & rules 2. Ceiling rates should be as approved by committee constituted under Rule 17(3) of RTPP Rules.
		JDC	Up to Rs. 50.00 Lacs	
9	To engage labour through service contractor in emergent conditions.	DE	Up to Rs. 5.00 Lacs	Note: - 1. As per the provisions of RTPP Act & Rules. 2. For Exceptionally emergent cases only like flood, Fire, earth quake, cyclones, lands sliding, breach of canals, pipe lines & roads with prior approval of JDC. Such labour shall not be employed on regular duties of a department such as office peons/ orderlies/ chowkidars etc. 3. The rate of daily wages
		ACE	Upto Rs 3.50 Lacs	
		SE	Up to Rs. 2.50 Lacs	
		EE	Up to Rs. 1.00 Lac	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				shall not exceed 20% of the minimum wages of the area concerned, otherwise approval of the next higher authority will necessarily be obtained. 4. Work done by such labour shall be entered in M.B., Wherever susceptible of measurement, besides, attendance register, otherwise, a certificate by EE shall be recorded of work being unsusceptible of measurements.
10	To rescind contracts, where such cancellation does not result in any loss to the JDA.	EC/JDC/D E/SE	Full Power	1. Full power to the limit of his power to acceptances of contracts. 2. Certificate of no loss should be recorded by Bid sanctioning Authority
11	To communicate and implement the decision of the standing committee constituted for settlement of disputes under "Condition of Contract"	JDC	Full Power	Note :- Standing Committee comprising of the followings would decide the matter within 60 days. JDC DL DE DF Sec. SE Concern (Member Secretary)
12	To divert savings out of provision for contingencies to meet cost of any new work or repair, not provided for in the estimate, provided such diversion does not materially alter the design provided in the original estimates sanctioned by a higher authority and is in respect of the work fairly contingent upon the work itself.	EC	Full Power	

SB

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
13	To transfer ascertained savings from any one portion of the project to another, within the sanctioned estimate,	JDC	Full Power	Note 1. Procurement shall be done as per RTPP Act & rules 2. Ceiling rates should be as approved by committee constituted under Rule 17(3) of RTPP Rules.
14	To permit deposit with other Govt. Deptts. Such as PHED, JVVNL, Municipalities or any other Deptts/ Board subject to administrative, financial approval of project being available.	JDC	Full Power	With consultation with DF These powers shall be exercised subject to following conditions: - Note: - 1. Deposits may be accepted in lump sum or in installments on prescribed dates as mutually agreed after ensuring that full amount is provided for in the budget of the concerned organisation and installments would be paid on specified dates: 2. Deposit works involving share of JDA will be agreed/ sanctioned only with the concurrence of EC. Revised cost will also be borne in the same proportion as decided by EC. 3. Expenditure will be charged against and limited to the deposit received only, in no case it should exceed the deposit. 4. Percentage charges, as approved from time to time, shall be levied unless exempted by F.D.

Handwritten signature/initials

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
15	To issue notice for inviting Bid and advertise through DPIR/Samwad cell.	EE	Full Power	Note: - 1. Short term NIB should be approved /permitted by competent authority. 2. Provided A&FS and TS is available already
16	To grant permission to float short term bid	JDC	Full Power	As per RTPP rule 43(7)
17	To accept/Reject bids for the execution of sanctioned work or part of sanctioned work and for rate contracts (area) wise for repairs, maintenance and petty work, supply of material for these works.	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of DE, DF & Secretary.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of ACE,SE,CAO & EE.
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of SE, CAO & EE.
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of C.A.O. & EE, AEN
		EE	Rs. 50.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of AO/AAO, AEN & JEN
<p>These powers shall be exercised subject to following conditions :</p> <p>Note: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The amount shown above are Bid amount quoted by the contractor which is intended to be sanctioned. 2. Bids will be invited & processed strictly as per the provisions of R.T.T.P. Act & Rules. Conditions (General/Special) of the bid documents shall not go against the provisions of RTPP Act & Rules. 3. These powers are subject to condition that the contractor's Bid amount do not exceed the amount of G-Schedule/Bill of Quantities/Activity Schedule (as per sanctioned estimates amount) by more than 10% and also that the overall monetary limits of financial powers mentioned above against each authority are not exceeded. 4. Thus both the conditions should be satisfied (i) that contractor's Bid amount must be within limits prescribed above and (ii) Bid premium/ percentage of contractor's Bid amount over sanctioned estimate amount of G-Schedule is upto 10%. 5. If the Bid amount of the contractor exceeds the estimated 				

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
				<p>amount of the work by more than 10% the powers will be exercised by the next higher authority. Where 'G' Schedule is based on a pervious year's BSR and Bid received when evaluated to the current BSR, applicable on the date of opening of Bid do not show any increase over the such evaluated estimated amount and Bid amount is within financial limits to sanction Bid as indicated each, the Bid need not be referred to nest higher authority provided the revised estimates has been prepared and submitted to competent authority to sanction and copy of the revised estimate have been enclosed with the Bid. Mere revision of BSR do not qualify to use this provision.</p> <p>6. If only single qualified/ responsive bid is received in response to a NIB, Same procument committee will be competent to sanction as per the provision of RTPP Act & Rules. (Rule 68) (2) (3) (Amended wide Letter & date 06-08-2018)</p> <p>7. These powers will be exercised only after examination and written comments of the concen Accounts Personnel as laid down in general conditions of these powers.</p> <p>8. Rates of Non-BSR items shall however be approved by the DE before inviting bids.</p> <p>9. Bid sancting authority/Higher authority & appellant Authority can reject the bid.</p>
17 A	Opening of Bid of single envelop system	Committ ee comprisi ng of Ex. En. A.En. & A.O./A. A.O.	Full Power	<ul style="list-style-type: none"> - Subject to fulfill condition of PWF&AR & RTPP Act & rules - Formation of the committee's under rule 03 of RTPP
17 B	Opening of two/three bid system	Committ ee comprisi ng of Ex. En. A.En. & A.O./A. A.O.	Full Power	
17 C	Technical Evaluation of two/three bid system	Committ ee comprisi ng of ACE/S. E. CAO	Full Power	

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
		& Ex. En.		
18	To undertake negotiations	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	Note:- The process shall be strictly undertaken according to rule 69 of RTPPR 2013.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Rs. 50.00 Lacs	
19	Bids have to finalized within mentioned period, after this period same authority shall exercise the power with recorded reasons.	JDC	50 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPP Rule 2013 shall be strictly followed. Also Read with RTPP rule 70 (2),48(1)(2)(3) & Amendmend of 06-08-2018 in rule 40(2)
		DE	45 days	
		ACE	35 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	
20	To withdraw work from the contractor under relevant clause of agreement, for recorded reason provided such withdrawal does not result into an unauthorised aid to contractor.	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	Note:- 1. Powers shall be exercised with concurrence of corresponding PC.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Rs. 50.00 Lacs	
21	To sanction running rate contract for works to be executed under piece work agreement, after calling division wise bids for the specific purpose.	DE	Full Power	As per rule 27 of RTPPR
22	To issue work order/permission to issue work order for original or repairs work up to the sanctioned estimated rates based on BSR when no tender are received. (Work order system)	EE	Up to Rs. 2.00 Lac on each occasion subject to Annual limit of Rs. 5.00 Lacs.	Note:- (1). Subject to overall limit of Rs. 10.00 lacs during a financial year for each zone/division. (2). As per RTPP Rule 2013 (Rule 27) & Rule 323 of PWF&AR
23	To Approve basic schedule of rates (BSR)	DE	Full power	Note: - 1. These powers will be exercised by the DE only

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
				<p>on the detailed recommendation of a Task Force in which DF will invariably be member. The Task Force will standardize various analysis of rates of components and determine rates on the basis of data/rates furnished by the SE/Zone level officers or other works departments</p> <p>2. BSR should be revised annually. Timely action shall be initiated so that the new BSR be made effective from the start of new financial year.</p> <p>3. Those Non-BSR items which are of regular use for the department must be brought into the list of BSR items regularly.</p>
24	To enlist contractor for various type of works as per Enlistment Rules of the Authority.	<p>JDC - AA class - E-xy-I class</p> <p>DE - A,B class - E-xy-II class</p> <p>SE - C,D class - E-xy-III, IV class</p>	The performance of the contractor shall be reviewed at the end of each financial year. On receipt of confidential report from the officers under whom he has worked in the last financial year for quality of works, ability to complete the work in the stipulated time, financial capacity and behavior towards officers	<p>Enlistment will be done as per PWF&AR until enlistment rules of Authority are made.</p> <p>Concerning matter should be routed through Director Finance for AA Class Contractors, CAO for A, B Class Contractors and AO/AAO for C, D Class Contractors.</p>

SR

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
			and staff of the authority as well as other relevant yard stick fixed by the Authority.	
25	To sanction execution and payment for extra items (BSR+Non BSR) as per Bidding documents/conditions of contract.	Bid Sanct ionin g Auth ority	Upto 5% of the of original Contract value as per RTPP Rule 73(2) order date 16-02-2018	<p>These powers shall be exercised subject to the following: -</p> <p>Note: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed the administrative and financial sanction for the work. 2. Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) do not exceed monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR+Non BSR) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority. 3. The extra items should be part and parcel of the work under execution and should be fairly contingent to it and therefore the execution of items of works of different nature or execution of items or work of similar nature of another reach/ site shall not be treated as extra item. 4. Total cost of all extra items shall not exceed the limits specified above. 5. Revised estimate have been got approved from the

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
				<p>competent authority if he items are not provided for in original estimates.</p> <p>6. Scale of accommodation or norms, types, designs sanctioned by higher authority are not exceeded.</p> <p>7. Material deviations from designs and scope of the Project will require approval of the original authority.</p> <p>8. The rates of Non-BSR items shall be got approved from the DE before sanction of extra items.</p> <p>9. The fair market value of such Extra Item payable by the procuring Entity to the contractor shall be determined by DE</p>
26	To sanction execution and payment of additional quantities of items existing in schedule-G or bill of quantities (BOQ) of a particular work. (Excess)	JDC	Up to 50% of the original contract amount.	<p>These powers shall be exercised subject to the following conditions: -</p> <p>Note: -</p> <p>1. Total amount of work including additional quantities & extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed 50% of the value of original contract in any case as per provision of RTPP Rule 73 (3).</p> <p>2. Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) should not exceed the administrative and financial sanction for the work.</p> <p>3. Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) shall not</p>
		DE	Up to 25% of the original contract amount.	
		ACE	Up to 10% of the original contract amount.	
		SE	Up to 8% of the original contract amount.	
		EE	Up to 5% of the original contract amount.	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR+Non BSR)) exceed the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority.</p> <p>4. The additional quantities should be part and parcel of the work under execution and therefore even the execution of works of different nature or execution of quantities/work of similar nature of another reach/site shall not be treated as additional quantity.</p> <p>5. Revised estimates, if required, have been approved by the competent authority.</p> <p>6. Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Executive committee concerned as follow :-</p> <p>(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be, recorded in writing.</p>

5/2

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
				<p>Wherever necessary, due to the quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities.</p> <p>(ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed.</p> <p>(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.</p> <p>7. order for additional quantity may be placed, if allowed in bidding documents/contract and the original order was given after inviting open competitive bids.</p>
27	To grant provisional time extension to the agreements, to keep the agreement alive.	EE	Full power, with recorded reasons	1. Written application for the same may produce by contractor/As per requirement of JODA
28	To grant for recorded reasons, final extension of time for the execution of works or supply of materials or other performances of the contract. & to lavy final liquidates damages in cases of delay.			Note: - 1. For reachwise / spanwise interim time extension in case, time spans/ reaches have been prescribed in the agreement for prorata progress, the bid sanctioning authority shall have full powers as per provisions of rules.
	(i) For a final extension of time which results in slippage upto 1.5 times of the stipulated work order duration.	Bid Sanct ionin g Auth ority	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	2. In case, extension of time involves payment of price escalation approval of EC shall be obtained.
	(ii) For a final extension of time which results in slippage upto two times of the stipulated work order	Next highe r Auth	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does	3. Hindrance Register shall be maintained by Engineer incharge and reasons for delay (on account of

S.NO	Nature of Power	To who m deleg ated	Power	Remark
	duration.	ority of the Bid Sanct ionin g Auth ority	not involve payment of price escalation.	department/ contractor) shall be specifically recorded eventwise with full details. Every extension case must accompany copy of Hindrance Register and the record of corrective measures taken by Engineer incharge.
	(iii) For a final extension of time which results in slippage more than two times of the stipulated work order duration.	JDC	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	4. When JDC in procuring committee the power of 28 (II) & (III) will be vest in E.C. 5. When EC itself procuring committee the power of 28 (II) & (III) will be also vest in E.C.
29	To sanction repayment of Security Deposits/Performance Security including PG from contractor on satisfactory completion of original and repair works after the lapse of the period, as specified in the contract.	EE	Full power	After issue Completion Certificate by concern XEN & that defects pointed out by any higher/authority/other have been removed by contractor
30	To execute the instruments relating to acceptance of bids on behalf the JDC.	EE	Full power	
31	To accept bonds of auctioneers & security bonds for the due performance and completion of work.	EE	Full power	
32	To remit or reduce or revise for recorded reasons the amount of compensation provided in the agreement.	EC JDC	Full power Up to Rs. 50 lacs	With consultation of DF.
33	To Procure through single source method under rule 17 of RTPP	JDC	FULL POWER	On recommendation of PC comprising of DE, DF & Secretary.

31/2

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
		Secretary	Up to Rs. 8.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of DE, DF & SE.
		DE	Up to Rs. 5.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of CAO, SE, XEN
34	To Procure through spot purchase method under rule 25 of RTPP	Secretary	FULL POWER	spot purchase committee comprising AO/AAO, XEN, AEN Concern
35	To Analysis the rate & approval of technical specification	DE	FULL POWER	On recommendation & Justification of PC comprising of SE, XEN
36	To approve Public private participation projects such as B.O.T./Swiss challenge method.	EC	Full Power	In accordance with RTPP Rules 79(A).
37	To sanction payment of price variation under clauses of agreement. (Under clause-45 of agreement)	DE	Full Power (For the work done within original stipulated completion period of work)	Note :- 1. For work done beyond stipulated original period of completion of the work or a portion of work or a portion of (Reach), the payment of escalation will be made after sanction of final extension in completion period by the competent authority. 2. The escalation will be granted as per conditions laid down in the agreement in relevant clauses. 3. No escalation will be granted on the basis of provisional price indices or provisional time extension. 4. Negative Price Variation (If any) Shall also be Calculate before find payment as per PWF&AR Provision.
38	Physical verification of works and inspection for Quality control measures	DE	Full Power	Assisted by ACE/SE
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	Assisted by SE
		SE	Up to Rs.	Assisted by EE

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
			150.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 50.00 Lacs	Note 1. Agreement - Amount is more than 25 Lacs than I & final, III, V and every Alternate Bill will be produced to ACE/DE for approval before the Payment.
39	Third party inspection regarding Quality Control	DE	Full Power	Note 1. This clause shall be applicable to all type of works involving outlay of Rs. 50.00 lac or more. 2. Selection of third party & payment thereof will depend on the nature of work which shall be discretionary on the part of DE with concurrence of DF. 3. Concerning Executive Engineer shall be responsible for carrying out inspection.
40	Component of sanction estimate for clause 45 of agreement must be approved by	DE		The components of sanction estimate for price escalation purpose are to be got sanctioned from DE. It is mandatory for EE concern to ensure that component decided are correct & has been examined by accounts person of corresponding PC.
41	To issue work Experience Certificate/ completion certificate	DE	Above Rs 300.00 Lacs	The Technical officer will issue completion certificate after completion of work.
		ACE	Upto Rs 250.00 Lacs	
		SE	Upto Rs 200.00 Lacs	
		XEN	Upto Rs 50.00 Lacs	
42	Budget Re appropriation	Auth ority	FULL POWER	On recommendation of JDC, DF, DE

STC

Part - II (Goods & Services)

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS				
1	To accord Administrative & financial approval for Goods & Services	EC.	Above 100 lacs	Note:- 1. Demand for such purchase will be determined by OIC Concern/Xen HQ/AEN HQ 2. Justification of demand for the same will be made by OIC of concern zone
		JDC	Upto Rs 100.00 lac	
		SEC.	Upto Rs 25.00 lac	
2	To accept/Reject bids for for Goods & servies	EC	Above 100 lacs	1. On the recommendation of PC Comprising JDC, DF,DE,Sec.
		JDC	Upto Rs 100.00 lacs	2. On the recommendation of PC Comprising DF,DE,Sec, Xen, HQ/ OIC Concern, Zone
		SEC.	Upto Rs 25.00 lac	3. On the recommendation of PC Comprising CAO Xen, HQ, AENHQ/ OIC Concern, Zone
3	To approve bidding document for good & services	JDC	Above 75.00 lacs	1. On recommendation of PC comprising of DF, DE, ACE, Secretary.
		SEC.	Upto 75.00 lacs	2. On recommendation of PC comprising of DE, CAO, SE, XEN.
		DE	Upto Rs 50.00 lac	3. On recommendation of PC comprising of ACE, CAO, SE, XEN .
		ACE	Upto Rs 25.00 lac	4. On recommendation of PC comprising of SE, CAO, XEN ,AEN
				Note- 1) PC will prepare bidding document with the discussion with expert 2) All the relevant rules, terms & conditions

STC

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				will incorporate which are according to policy of govt of Raj notification of FD, GF&AR, RTPP Act & Rules 3) Bidding document will be finalised after consult with the committee here by for the procurement according to the policy of GOR for the promotion of SMME
4	To levy final liquidated damages in cases of delay in supplies of goods & services.			
	(i) In cases where actual work completion duration has been upto 1.5 times of original stipulated work order duration.	Bid sanctioning Authority	Full Power	Note: - These powers are not applicable for interim liquidated damages.
	(ii) In cases where actual work completion duration has been upto two times of original stipulated work order duration.	Next higher Authority of bid sanctioning Authority	Full Power	
	(iii) In cases where actual work completion duration has been more than two times of original stipulated work order duration.	JDC	Full Power	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
5	To sanction advance for purchase of store (i) In case of R/C	DE	Up to 98% of the cost of goods Up to 90% of the cost of goods worth Rs. Three Lacs.	Subject to approval of JDC
			Note a) Advance for purchase of stores may be given in exceptional circumstances taking necessary	

STC

			<p>precaution for securing the financial interest of JDA.</p> <p>b) Such advance should be made on submission of Railway or Road Transport Receipts. The balance should be paid on receipts of the goods subject to the usual verification.</p> <p>c) The advances payment should preferably be made on receipt of a certificate of personal inspection of goods by the consignee who may employ an officer not below the rank of an Assistant Engineer.</p> <p>d)) It should also be made clear to the suppliers that they are in no way absolved from the responsibility in respect of quality and quantity of stores dispatched by them and recoveries are liable to be made if the stores received are found in way to be defective or short in quantity.</p> <p>e) Inspection before dispatch of good/article shall be ensured where the advance payment amount 75% of the order placed and exceed Rs. 50000/-</p>
6	To sanction purchase of spare parts of a particular make for machine from the manufacturer or original equipments supplier of from the sole distributors.	DE	Up to Rs. 2.00 Lacs (beyond this limit tender should be invited)
7	To Purchase of spare parts after inviting limited tenders of a particular machine from the firms approved by the JDC in case where the material is not supplied with in the delivery period by the rate contractor.	Dir. Engg. EE	Up to Rs. 1.00 Lacs in each case Up to Rs. 0.25 Lacs in each case with annual limit of Rs. 1.00 Lacs
8	To sanction purchase of spare parts in emergent cases, without inviting tenders.	EE	Up to Rs. 0.50 Lacs. (maximum annual limit-Rs. 2.00 Lacs)
9	To pass indents on other department articles	EE	Full power

Note

1. Prior A&FS from JDC will be mandatory.
2. As per procedure laid down in RTPPR-32 and relevant notification dated 04.09.2013.

	required for sanctioned works.			
10	To sanction the limits of Reserve stocks of divisions	JDC	Full power	
11	To sanction estimates for repair and carriage of tools and plants subject to specific A&F.	DE	Full power	
		SE	Up to Rs. 1.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 0.50 Lacs	
12	To accept bids for the sale of tools and plants declared surplus by the competent authority in accordance with rules.	JDC	Full power	As per procedure laid down in rule 16 to 27 of GF&AR vol I part II.
		DE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		ACE	Up to Rs. 50.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 25.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 5.00 Lacs	
13	To issue stock or other materials to works at stock or market rates whichever is greater when their issue is not provided for in the contract.	EE	Full power subject to the condition that a report should be made to DE and DF stating the amount of the issue and the circumstances require it.	
14	To declare any stores (including tools & plants stocks and materials received from work dismantled) as surplus or unserviceable and sanction their sale by public auction or destruction.	DE	Full power	Note: - 1. These monetary limits refer to original purchase price which may be estimated if original price is not known. 2. Relevant provisions of GF&AR shall be <i>mutatis mutandis</i> adhered to.
		EE	Up to Rs. 0.50 Lacs.	
			Note: A report should be made to the Director (Finance). Detailed survey report shall be prepared and verified by committee.	
15	To sanction rate for hiring of departmental tool & plans	DE	Full power subject to rules	With prior concurrence from JDC
16	To sanction rate for hiring of departmental tool & plants and other materials obtained for external sources.	EE	Full power for each type of machine Rs. 10000/- only in emergent case after recording reasons.	With prior concurrence from JDC
17	To approve and counter sign indents for instruments mathematical	DE	Full power	
		EE	Full power if within the scale sanctioned for the	

31

	instruments, office calculator etc.		division.	
18	To sanction after due investigation the write off value of all type of stores, and plant lost destroyed or damaged by accident, negligence, and fraud or otherwise.	JDC	Full power	As per GF&AR Volume I part II Rule 20
		DE	Up to Rs. 3.00 Lacs in each case	
		ACE	Up to Rs. 2.00 Lacs in each case	
		SE	Up to Rs.1.00 lacs in each case	
		EE	Up to Rs.5,000/- each case	
19	To sanction the write off tool and plants which have become unserviceable after fair wear and tear.	DE	Full power	Subject to GF&AR Volume I part II Rule 17,18
20	To sanction after due investigation the write off of measurement books muster role which have been lost.	DE	Full Power	Note: 1. In each case while ordering write off the DE should pass a separate order after due Investigation & compliance of rules giving full details. Copy of the order should be endorsed to Director.(Finance) and JDC. 2. FIR must be done
21	To sanction estimates for losses on stock due to depreciation owing to a fall in prices or any cause or adjustment of losses on manufacturers accounts.	JDC	Full Power	
		DE	Up to Rs.0.50 lacs	
		SE	Up to Rs .20 lacs	
22	To write off discrepancies in accounts	EE	Up to Rs.50/-	
23	To Write off Infractionous expenditure on construction.	DE	1% of the contract value subject to a ceiling of Rs.50,000/- in consultation with Director(Fin.)	
24	To sanction compensation for the lands and crops standing on the land taken over	JDC	Full Power	
		DE	Rs. 5.00 lace	

3/2

	by the authority for public works by negotiations provided amount is certified by land acquisition are reasonable and not excessive.	EE	Up to Rs. 0.50 lacs. For each case.	
25	To sanction compensation, under the workmen's compensation Act of under any other law for the time being of in force on as prescribed under the rules.	JDC	Full Power	Note:- If the award is pending for sanction before Competent authority. Director Engineering and SE may sanction an advance payment up to 75% of the compensation payable.
		DE	Up to Rs.2.00 lacs	
		ACE	Up to Rs.1.50 lacs	
		SE	Up to Rs.1.00 lacs	
		EE	Up to Rs.0.50 lacs	

Note -

1. This Schedule of Powers shall come in to force from 1st day of May 2017 & amended on..... upon all work orders and agreements which are live and ongoing on that day.
2. Any matter not covered in this Schedule of Powers shall be exercised as per RTPP Act 2012&Rules 2013.
3. Any change in RTPP act-2012, Rule 2013, PWF&AR & GF&AR will supercede on this SOP

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का पद सृजित नहीं है। अतः शिड्यूल ऑफ पॉवर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को प्रदत्त शक्तियों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अनुसार संशोधित शिड्यूल ऑफ पॉवर को सर्व सम्मति से स्वीकृत/लागू करने का निर्णय लिया गया तथा निर्णयोपरान्त उक्त शिड्यूल ऑफ पॉवर को राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया:-

SOP Effective from 1st day of May 2017 (Revised on 18 May 2022)

Part - I (Works)

General Note:-

1. Estimates should be framed at prevailing BSR.
2. Rate analysis of works shall be prepared by concerned Ex En. and counter signed by Director Eng. Before opening of price bid of the tender.
3. All powers, which are not specified in the schedule below, involving financial implication up to Rs. 500.00 Lacs, shall vest with JDC.



4. For delegation of powers which are not covered in this schedule of powers shall be *mutatis mutandis* applied as per PWF & AR and RTPPR 2013.
5. Bid amount means the amount offered by the Bid/contractor intended to be sanctioned.
6. Estimated amount means sanctioned estimated amount of item of BOQ schedule of work concerned.
7. Bid premium means percentage rate above/below quoted by the tenderer over BOQ Schedule amount.
8. A financial power Or an authority, given under those rules, shall automatically vest in all higher authorities of that authority.
9. The financial power, not specifically delegated to any authority, shall vest with authority subject to RTPP Act & Rules.
10. No Administrative/Financial sanction shall be issued without appropriate budget provision. All sanctions shall be strictly restricted unto the limits of available Budget.
11. Wherever any specific power for a purpose has been given to an authority under this delegation, then it shall prevail over the general powers (if any) for that purpose.
12. The powers shall be subject to the budget provision in general and to the specific budget provisions, wherever mentioned in these delegations.
13. The powers contained in these delegations shall be subject to the rules and other provisions contained in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012; Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013. Time to Time Amendment in RTPP act & rule will be applicable as it is.
14. Splitting of works for the purpose of keeping bids in its own competence by any officer is an irregularity. Therefore, splitting of bids should not be resorted to. If however, in genuine cases, it becomes necessary in the interest of work to split up, it should be done only after obtaining prior permission of the authority competent to sanction the bid of work without split up. The competent authority shall, while according permission mention the reasons for splitting of works.
15. The powers shall exercised only after comments/examination by the senior most Accounts Personnel (Director Finance/ Chief Accounts Officer/ Senior Accounts Office/ Accounts Officer/ Assistant Accounts Officer) Posted in the Office. While conveying sanction, the reference of comments/examination by Accounts Personnel shall be mentioned. However, if the sanctioning authority differs with the advice of Accounts Personnel, the case must be submitted to next higher authority.
16. Wherever the words "bid amount" have been used in these powers, it means the amount offered by the bidder/ contractor which is intended to be sanctioned.
17. Wherever the words "estimated amount" are appearing, it means sanctioned estimated amount of items of G-Schedule or BOQ of the work concerned as the case may be.
18. "Bid premium" means percentage rate above/below quoted by the contractor over department rates or if worked out in item rates, the percentage of bid amount over sanctioned estimated amount for deciding competence to sanction bid.
19. Ensure that approved drawing & designs etc. are ready before NIB and land has been made over before sanction of Bid. Other actions required office level has been completed before sanction.
20. JDA shall prepare a procurement plan as per provision of Rule 7 of RTPP Rules, 2013.
21. Authority means the Jodhpur Development Authority constituted under section 3 of the Jodhpur Development Authority Act 2009.

ABBREVIATION	
EC : Executive Committee	GF & AR : General Financial & Accounts Rules
JDC : Jodhpur Development Commissioner	NIB : Notice Inviting Bid
DF : Director Finance	PPP : Public Private Partnership
DE : Director Engineering	PWF & AR : Public Works Financial & Accounts Rules
AE : Assistant Engineer	RTPP : Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013
AMC : Annual Maintenance Contract	SE : Superintending Engineer
AS : Administrative Sanction	T&P : Tools & Plant
BOT : Build- Operate & Transfer	TS : Technical Sanction
BSR : Basic Schedule of Rates	FS : Financial Sanction
CAO : Chief Accounts Officer	PC : Procurement Committee
EE : Executive Engineer	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS				
1	Administrative & Financial approval to execute a Project/Scheme/Works in whole or part including repairs and maintenance.	EC	FULL POWERS	Unless restricted by State Govt
		JDC	Up to Rs. 5.00 Crore	On recommendation Public works committee If Amt. is 50 lac & above
2	Revised Administrative & Financial approval to execute a Project/Scheme/ Works in whole or part including repairs and maintenance.	E.C. (Inclusive of Revised A&Fs)	Above Rs. 5.00 Crore Up to 50% of original value of the Contract	Note- (i) Revised estimate must be sanctioned by competent authority before the proposal for revised A&F (ii) As per RTPP Rule-73(3)(iii)
		JDC (Inclusive of Revised A&Fs)	Up to Rs. 5.00 Crore up to 50% of original value of the Contract	
3	Splitting of A & F Sanctions.	DE	Full power	(With Recommended of Bid Sanction Authority of work without split up) (see general note 14)
4	To permit undertaking contribution/ deposit works and to accept contribution/ deposit in respect of them.	EC	Full Power	These powers shall be exercised subject to following conditions: - Note: - 5. Deposits may be accepted in lump sum or in
		JDC	Up to Rs. 1000.00 Lacs	
		DE	Up to Rs. 300.00 Lacs	
		SE	Up to Rs.	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
			150.00 Lacs	installments on prescribed dates as mutually agreed after ensuring that full amount is provided for in the budget of the concerned organisation and installments would be paid on specified dates.
		EE	Up to Rs. 30.00 Lacs	
				6. Deposit works involving share of JDA will be agreed/sanctioned only with the concurrence of EC. Revised cost will also be borne in the same proportion as decided by EC.
				7. Expenditure will be charged against and limited to the deposit received only, in no case it should exceed the deposit.
				8. Percentage charges, as approved from time to time, shall be levied as decided in byelaws/administrative orders.

TECHNICAL SANCTIONS

5	To accord technical sanction to detailed original/revised or supplementary estimated based on A&F sanction already available for original work, deposit works contribution works subject to the condition that revised A&F shall be sought in Advance, If the revised as supplementing estimate exceed the original A&F	DE	Full Power	These powers shall be exercised subject to following conditions only: - Note: - 9. There is provision in the administrative approval to cover the particular type of work and sanction of the
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 50.00 Lacs	

Handwritten signature

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
	sanction by more than 10%			<p>detailed estimates does not result in excess of more than 10% over the provision under the particular sub-head of the administratively approved project estimate under which the estimate is sanctioned but it shall not exceed the administrative approval of the project as a whole.</p> <p>10. Revised estimate involving excess of more than 10% over original sanctioned estimate shall be submitted to the next higher authority for technical sanction after obtaining revised AS/FS from Competent Authority. Incase of CE is next higher authority will be CE himself (CE means Chief Engineer)</p> <p>11. If the cost of the work, according to the revised estimates, exceeds the limits of the powers to accord technical sanction, the revised estimate should be submitted to the next higher authority. In CE next high authority will be CE himself.</p> <p>12. Revised Administrative &</p>

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>Financial approval is obtained if revised cost is more than 10% of original cost.</p> <p>PWF&AR-286&287</p> <p>13. For supplementary estimate, the authority who sanctioned original estimate will be competent provided original plus supplementary is in his competence.</p> <p>14. No officer is competent to pass any excess over a revised estimate sanctioned by an authority higher than himself.</p> <p>15. For subsequent revision of estimate also, the amount of estimates shall form basis for revision.</p> <p>16. Rates of Non BSR items shall however be approved by the DE only.</p>
6	To accord administrative and technical approval/Terms of Reference's approval of a consultant and to approve bids for conducting of detailed surveys and investigation, preparation of designs and drawings, project formulation and preparation and other studies, appointing consultant, hiring of consultancy services etc., other than by department agency e.g. private consultancy services.	<p>EC</p> <p>JDC</p> <p>DE</p>	<p>Full Power up to 2% of the project cost.</p> <p>Up to Rs. 50.00 Lacs or 2% of the project cost whichever is less.</p> <p>Up to Rs. 15.00 Lacs or 2% of the project cost whichever is less.</p>	<p>Note: -</p> <p>5. A certificate is to be recorded by the Approving Authority that the departmental organisation existing for the work is either fully occupied or is not well equipped for the job.</p> <p>6. Procurement is made as per & RTPP Act/Rules. (PWF&AR-306A)</p> <p>7. Retired personnel will not be eligible</p>

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				for such assignments for two years after retirement, except with specific Government sanction. 8. There should be specific budget provision for this purpose.
7	To accept bids for works on Build, operate and Transfer (BOT) basis, PPP Projects including acceptance of bids for consultancy of these projects.	EC	Full Power	Guidelines set by state government should be followed
8	In emergent conditions like flood relief and other natural calamities, the subject matter of procurement may be procured upto the ceiling rates fixed by district level committee. Constituted under RTPPR-17(3)	EC	Up to Rs. 100.00 Lacs	Note 1. Procurement shall be done as per RTPP Act & rules 2. Ceiling rates should be as approved by committee constituted under Rule 17(3) of RTPP Rules.
		JDC	Up to Rs. 50.00 Lacs	
9	To engage labour through service contractor in emergent conditions.	DE	Up to Rs. 5.00 Lacs	Note: - 5. As per the provisions of RTPP Act & Rules. 6. For Exceptionally emergent cases only like flood, Fire, earth quake, cyclones, lands sliding, breach of canals, pipe lines & roads with prior approval of JDC. Such labour shall not be employed on regular duties of a department such as office peons/ orderlies/ chowkidars etc.
		SE	Up to Rs. 2.50 Lacs	
		EE	Up to Rs. 1.00 Lac	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>7. The rate of daily wages shall not exceed 20% of the minimum wages of the area concerned, otherwise approval of the next higher authority will necessarily be obtained.</p> <p>8. Work done by such labour shall be entered in M.B., Wherever susceptible of measurement, besides, attendance register, otherwise, a certificate by EE shall be recorded of work being unsusceptible of measurements.</p>
10	To rescind contracts, where such cancellation does not result in any loss to the JDA.	EC/JDC/DE/SE	Full Power	<p>3. Full power to the limit of his power to acceptances of contracts.</p> <p>4. Certificate of no loss should be recorded by Bid sanctioning Authority</p>
11	To communicate and implement the decision of the standing committee constituted for settlement of disputes under "Condition of Contract"	JDC	Full Power	<p>Note :- Standing Committee comprising of the followings would decide the matter within 60 days.</p> <p>JDC DL DE DF Sec. SE Concern (Member Secretary)</p>

327

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
12	To divert savings out of provision for contingencies to meet cost of any new work or repair, not provided for in the estimate, provided such diversion does not materially alter the design provided in the original estimates sanctioned by a higher authority and is in respect of the work fairly contingent upon the work itself.	EC	Full Power	
13	To transfer ascertained savings from any one portion of the project to another, within the sanctioned estimate,	JDC	Full Power	Note 1. Procurement shall be done as per RTPP Act & rules' 2. Ceiling rates should be as approved by committee constituted under Rule 17(3) of RTPP Rules.
14	To permit deposit with other Govt. Deptts. Such as PHED, JVVNL, Municipalities or any other Deptts/ Board subject to administrative, financial approval of project being available.	JDC	Full Power	With consultation with DF These powers shall be exercised subject to following conditions: - Note: - 5. Deposits may be accepted in lump sum or in installments on prescribed dates as mutually agreed after ensuring that full amount is provided for in the budget of the concerned organisation and installments would be paid on specified dates. 6. Deposit works involving share of JDA will be agreed/ sanctioned only with the concurrence of EC.

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>Revised cost will also be borne in the same proportion as decided by EC.</p> <p>7. Expenditure will be charged against and limited to the deposit received only, in no case it should exceed the deposit.</p> <p>8. Percentage charges, as approved from time to time, shall be levied unless exempted by F.D.</p>
15	To issue notice for inviting Bid and advertise through DPIR/Samwad cell.	EE	Full Power	<p>Note: -</p> <p>3. Short term NIB should be approved /permitted by competent authority.</p> <p>4. Provided A&FS and TS is available already</p>
16	To grant permission to float short term bid	JDC	Full Power	As per RTPP rule 43(7)
17	To accept/Reject bids for the execution of sanctioned work or part of sanctioned work and for rate contracts (area) wise for repairs, maintenance and petty work, supply of material for these works.	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of DE, DF & Secretary.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of SE, CAO & EE.
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of C.A.O. & EE, AEN
		EE	Rs. 50.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of AO/AAO, AEN & JEN
<p>These powers shall be exercised subject to following conditions :</p> <p>Note: -</p> <p>10. The amount shown above are Bid amount quoted by the contractor which is intended to be sanctioned.</p> <p>11. Bids will be invited & processed strictly as per the provisions of R.T.T.P. Act & Rules. Conditions (General/Special) of the bid documents shall not go against the provisions of RTPP Act & Rules.</p> <p>12. These powers are subject to condition that the contractor's</p>				

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
		<p>Bid amount do not exceed the amount of G-Schedule/Bill of Quantities/Activity Schedule (as per sanctioned estimates amount) by more than 10% and also that the overall monetary limits of financial powers mentioned above against each authority are not exceeded.</p> <p>13. Thus both the conditions should be satisfied (i) that contractor's Bid amount must be within limits prescribed above and (ii) Bid premium/ percentage of contractor's Bid amount over sanctioned estimate amount of G-Schedule is upto 10%.</p> <p>14. If the Bid amount of the contractor exceeds the estimated amount of the work by more than 10% the powers will be exercised by the next higher authority. Where 'G' Schedule is based on a pervious year's BSR and Bid received when evaluated to the current BSR, applicable on the date of opening of Bid do not show any increase over the such evaluated estimated amount and Bid amount is within financial limits to sanction Bid as indicated each, the Bid need not be referred to nest higher authority provided the revised estimates has been prepared and submitted to competent authority to sanction and copy of the revised estimate have been enclosed with the Bid. Mere revision of BSR do not qualify to use this provision.</p> <p>15. If only single qualified/ responsive bid is received in response to a NIB, Same procurement committee will be competent to sanction as per the provision of RTPP Act & Rules. (Rule 68) (2) (3) (Amended wide Letter & date 06-08-2018)</p> <p>16. These powers will be exercised only after examination and written comments of the concen Accounts Personnel as laid down in general conditions of these powers.</p> <p>17. Rates of Non-BSR items shall however be approved by the DE before inviting bids.</p> <p>18. Bid sancting authority/Higher authority & appellant Authority can reject the bid.</p>		
17 A	Opening of Bid of single envelop system	Committee comprising of Ex. En. A.En. & A.O./A.A.O.	Full Power	<ul style="list-style-type: none"> - Subject to fulfill condition of PWF&AR & RTPP Act & rules - Formation of the committee's under rule 03 of RTPP
17 B	Opening of two/three bid system	Committee comprising of Ex. En. A.En. & A.O./A.A.O.	Full Power	
17 C	Technical Evaluation of two/three bid system	Committee comprising of S.E. CAO & Ex. En.	Full Power	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
18	To undertake negotiations	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	Note:- The process shall be strictly undertaken according to rule 69 of RTPPR 2013.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Rs. 50.00 Lacs	
19	Bids have to finalized within mentioned period, after this period same authority shall exercise the power with recorded reasons.	JDC	50 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPP Rule 2013 shall be strictly followed. Also Read with RTPP rule 70 (2),48(1)(2)(3) & Amendmend of 06-08-2018 in rule 40(2)
		DE	45 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	
20	To withdraw work from the contractor under relevant clause of agreement, for recorded reason provided such withdrawal does not result into an unauthorised aid to contractor.	JDC	Above Rs. 500.00 Lacs	Note:- 2. Powers shall be exercised with concurrence of corresponding PC.
		DE	Up to Rs. 500.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		EE	Rs. 50.00 Lacs	
21	To sanction running rate contract for works to be executed under piece work agreement, after calling division wise bids for the specific purpose.	DE	Full Power	As per rule 27 of RTPPR
22	To issue work order/permission to issue work order for original or repairs work up to the sanctioned estimated rates based on BSR when no tender are received. (Work order system)	EE	Up to Rs. 2.00 Lac on each occasion subject to Annual limit of Rs. 5.00 Lacs.	Note:- (1). Subject to overall limit of Rs. 10.00 lacs during a financial year for each zone/division. (2). As per RTPP Rule 2013 (Rule 27) & Rule 323 of PWF&AR
23	To Approve basic schedule of rates (BSR)	DE	Full power	Note: - 4. These powers will be exercised by the DE only on the detailed recommendation of a Task Force in which DF will invariably be member. The Task

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>Force will standardize various analysis of rates of components and determine rates on the basis of data/rates furnished by the SE/Zone level officers or other works departments</p> <p>5. BSR should be revised annually. Timely action shall be initiated so that the new BSR be made effective from the start of new financial year.</p> <p>6. Those Non-BSR items which are of regular use for the department must be brought into the list of BSR items regularly.</p>
24	To enlist contractor for various type of works as per Enlistment Rules of the Authority.	<p>JDC - AA class - E-xy-I class</p> <p>DE - A,B class - E-xy-II class</p> <p>SE - C,D class - E-xy-III, IV class</p>	The performance of the contractor shall be reviewed at the end of each financial year. On receipt of confidential report from the officers under whom he has worked in the last financial year for quality of works, ability to complete the work in the stipulated time, financial capacity and behavior towards officers	<p>Enlistment will be done as per PWF&AR until enlistment rules of Authority are made.</p> <p>Concerning matter should be routed through Director Finance for AA Class Contractors, CAO for A, B Class Contractors and AO/AO for C, D Class Contractors.</p>

31/1

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
			and staff of the authority as well as other relevant yard stick fixed by the Authority.	
25	To sanction execution and payment for extra items (BSR+Non BSR) as per Bidding documents/conditions of contract.	Bid Sanctioning Authority	Upto 5% of the of original Contract value as per RTPP Rule 73(2) order date 16-02-2018	<p>These powers shall be exercised subject to the following: -</p> <p>Note: -</p> <p>10. Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed the administrative and financial sanction for the work.</p> <p>11. Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) do not exceed monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR+Non BSR) exceeds the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority.</p> <p>12. The extra items should be part and parcel of the work under execution and should be fairly contingent to it and therefore the execution of items of works of different nature or execution of items or work of similar nature of another reach/ site</p>

JKL

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>shall not be treated as extra item.</p> <p>13. Total cost of all extra items shall not exceed the limits specified above.</p> <p>14. Revised estimate have been got approved from the competent authority if he items are not provided for in original estimates.</p> <p>15. Scale of accommodation or norms, types, designs sanctioned by higher authority are not exceeded.</p> <p>16. Material deviations from designs and scope of the Project will require approval of the original authority.</p> <p>17. The rates of Non-BSR items shall be got approved from the DE before sanction of extra items.</p> <p>18. The fair market value of such Extra Item payable by the procuring Entity to the contractor shall be determined by DE</p>
26	To sanction execution and payment of additional quantities of items existing in schedule-G or bill of quantities (BOQ) of a particular work. (Excess)	JDC	Up to 50% of the original contract amount.	<p>These powers shall be exercised subject to the following conditions: -</p> <p>Note: -</p> <p>8. Total amount of work including additional quantities & extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed 50% of the value of original contract in</p>
		DE	Up to 25% of the original contract amount.	
		SE	Up to 8% of the original contract amount.	
		EE	Up to 5% of the original contract	

JRL

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
			amount.	<p>any case as per provision of RTPP Rule 73 (3).</p> <p>9. Total amount of the work including additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) should not exceed the administrative and financial sanction for the work.</p> <p>10. Total amount of work i.e. tendered amount plus cost of additional quantities and extra items (BSR+Non BSR) shall not exceed the monetary limit to accept bid. If the total amount (including additional and extra items (BSR+Non BSR)) exceed the monetary limit to accept bid, the matter shall be referred to next higher authority.</p> <p>11. The additional quantities should be part and parcel of the work under execution and therefore even the execution of works of different nature or execution of quantities/work of similar nature of another reach/site shall not be treated as additional quantity.</p> <p>12. Revised estimates, if required, have been approved by the</p>

JKZ

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				<p>competent authority.</p> <p>13. Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Executive committee concerned as follow :-</p> <p>(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be, recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities.</p> <p>(ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed.</p> <p>(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any</p>

जेए

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				case. 14. order for additional quantity may be placed, if allowed in bidding documents/contract and the original order was given after inviting open competitive bids.
27	To grant provisional time extension to the agreements, to keep the agreement alive.	EE	Full power, with recorded reasons	2. Written application for the same may produce by contractor/As per requirement of JODA
28	To grant for recorded reasons, final extension of time for the execution of works or supply of materials or other performances of the contract. & to levy final liquidates damages in cases of delay.			Note: - 6. For reachwise / spanwise interim time extension in case, time spans/reaches have been prescribed in the agreement for prorata progress, the bid sanctioning authority shall have full powers as per provisions of rules. 7. In case, extension of time involves payment of price escalation approval of EC shall be obtained. 8. Hindrance Register shall be maintained by Engineer incharge and reasons for delay (on account of department/ contractor) shall be specifically recorded eventwise with full details. Every extension case must accompany copy of Hindrance Register and the record of corrective measures taken by Engineer
	(i) For a final extension of time which results in slippage upto 1.5 times of the stipulated work order duration.	Bid Sanctioning Authority	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	
	(ii) For a final extension of time which results in slippage upto two times of the stipulated work order duration.	Next higher Authority of the Bid Sanctioning Authority	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	
	(iii) For a final extension of time which results in slippage more than two times of the stipulated work order duration.	JDC	Full Power as per "Condition of Contract" provided it does not involve payment of price escalation.	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				incharge. 9. When JDC in procuring committee the power of 28 (II) & (III) will be vest in E.C. 10. When EC itself procuring committee the power of 28 (II) & (III) will be also vest in E.C.
29	To sanction repayment of Security Deposits/Performance Security including PG from contractor on satisfactory completion of original and repair works after the lapse of the period, as specified in the contract.	EE	Full power	After issue Completion Certificate by concern XEN & that defects pointed out by any higher/authority/other have been removed by contractor
30	To execute the instruments relating to acceptance of bids on behalf the JDC.	EE	Full power	
31	To accept bonds of auctioneers & security bonds for the due performance and completion of work.	EE	Full power	
32	To remit or reduce or revise for recorded reasons the amount of compensation provided in the agreement.	EC JDC	Full power Up to Rs. 50 lacs	With consultation of DF
33	To Procure through single source method under rule 17 of RTPP	JDC	FULL POWER	On recommendation of PC comprising of DE, DF & Secretary.
		Secretary	Up to Rs. 8.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of DE, DF & SE.
		DE	Up to Rs. 5.00 Lacs	On recommendation of PC comprising of CAO, SE, XEN
34	To Procure through spot purchase method under rule 25 of RTPP	Secretary	FULL POWER	spot purchase committee comprising AO/AAO, XEN, AEN Concern

JKL

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
35	To Analysis the rate & approval of technical specification	DE	FULL POWER	On recommendation & Justification of PC comprising of SE, XEN
36	To approve Public private participation projects such as B.O.T./Swiss challenge method.	EC	Full Power	In accordance with RTPP Rules 79(A).
37	To sanction payment of price variation under clauses of agreement. (Under clause-45 of agreement)	DE	Full Power (For the work done within original stipulated completion period of work)	Note :- 5. For work done beyond stipulated original period of completion of the work or a portion of work or a portion of (Reach), the payment of escalation will be made after sanction of final extension in completion period by the competent authority. 6. The escalation will be granted as per conditions laid down in the agreement in relevant clauses. 7. No escalation will be granted on the basis of provisional price indices or provisional time extension. 8. Negative Price Variation (If any) Shall also be Calculate before find payment as per PWF&AR Provision.
38	Physical verification of works and inspection for Quality control measures	DE	Full Power	Assisted by SE
		SE	Up to Rs. 150.00 Lacs	Assisted by EE
		EE	Up to Rs. 50.00 Lacs	Note 2. Agreement Amount is more than 25 Lacs than I & final, III, V

जेए

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				and every Alternate Bill will be produced to DE for approval before the Payment.
39	Third party inspection regarding Quality Control	DE	Full Power	Note 4. This clause shall be applicable to all type of works involving outlay of Rs. 50.00 lac or more. 5. Selection of third party & payment thereof will depend on the nature of work which shall be discretionary on the part of DE with concurrence of DF. 6. Concerning Executive Engineer shall be responsible for carrying out inspection.
40	Component of sanction estimate for clause 45 of agreement must be approved by	DE	Full Power	The components of sanction estimate for price escalation purpose are to be got sanctioned from DE. It is mandatory for EE concern to ensure that component decided are correct & has been examined by accounts person of corresponding PC.
41	To issue work Experience Certificate/ completion certificate	DE	Above Rs 300.00 Lacs	The Technical officer will issue completion certificate after completion of work.
		SE	Upto Rs 200.00 Lacs	
		XEN	Upto Rs 50.00 Lacs	
42	Budget Re appropriation	Authority	FULL POWER	On recommendation of JDC, DF, DE



Part - II (Goods & Services)

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS				
1	To accord Administrative & financial approval for Goods & Services	EC	Above 100 lacs	Note: 3. Demand for such purchase will be determined by OIC Concern/Xen HQ/AEN HQ 4. Justification of demand for the same will be made by OIC of concern zone.
		JDC	Upto Rs 100.00 lac	
		SEC.	Upto Rs 25.00 lac	
2	To accept/Reject bids for for Goods & servies	EC	Above 100 lacs	4. On the recommendation of PC Comprising JDC, DF,DE,Sec.
		JDC	Upto Rs 100.00 lacs	5. On the recommendation of PC Comprising DF,DE,Sec, Xen, HQ/ OIC Concern, Zone
		SEC.	Upto Rs 25.00 lac	6. On the recommendation of PC Comprising CAO Xen, HQ, AENHQ/ OIC Concern, Zone
3	To approve bidding document for good & services	JDC	Above 75.00 lacs	5. On recommendation of PC comprising of DF, DE, Secretary.
		SEC.	Upto 75.00 lacs	6. On recommendation of PC comprising of DE, CAO, SE, XEN.
		DE	Upto Rs 50.00 lac	7. On recommendation of PC comprising of CAO, SE, XEN .
				Note- 4) PC will prepare bidding document with the discussion with expert 5) All the relevant rules, terms & conditions will

JPC

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
				Incorporate which are according to policy of govt of Raj notification of FD, GE&AR RTPP Act & Rules 6) Bidding document will be finalised after consult with the committee here by for the procurement according to the policy of GOR for the promotion of SMME
4	To levy final liquidated damages in cases of delay in supplies of goods & services.			
	(i) In cases where actual work completion duration has been upto 1.5 times of original stipulated work order duration.	Bid sanctioning Authority	Full Power	Note: - These powers are not applicable for interim liquidated damages.
	(ii) In cases where actual work completion duration has been upto two times of original stipulated work order duration.	Next higher Authority of bid sanctioning Authority	Full Power	
	(iii) In cases where actual work completion duration has been more than two times of original stipulated work order duration.	JDC	Full Power	

S.NO	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
5	To sanction advance for purchase of store (i) In case of R/C	DE	Up to 98% of the cost of goods Up to 90% of the cost of goods worth Rs. Three Lacs.	Subject to approval of JDC
			Note f) Advance for purchase of stores may be given in exceptional	

			<p>circumstances taking necessary precaution for securing the financial interest of JDA.</p> <p>g) Such advance should be made on submission of Railway or Road Transport Receipts. The balance should be paid on receipts of the goods subject to the usual verification.</p> <p>h) The advances payment should preferably be made on receipt of a certificate of personal inspection of goods by the consignee who may employ an officer not below the rank of an Assistant Engineer.</p> <p>i)) It should also be made clear to the suppliers that they are in no way absolved from the responsibility in respect of quality and quantity of stores dispatched by them and recoveries are liable to be made if the stores received are found in way to be defective or short in quantity.</p> <p>j) Inspection before dispatch of good/article shall be ensured where the advance payment amount 75% of the order placed and exceed Rs. 50000/-</p>	
6	To sanction purchase of spare parts of a particular make for machine from the manufacturer or original equipments supplier of from the sole distributors.	DE	Up to Rs. 2.00 Lacs (beyond this limit tender should be invited)	<p>Note</p> <p>3. Prior A&FS from JDC will be mandatory.</p> <p>4. As per procedure laid down in RTPPR-32 and relevant notification dated 04.09.2013.</p>
7	To Purchase of spare parts after inviting limited tenders of a particular machine from the firms approved by the JDC in case where the material is not supplied with in the delivery period by the rate contractor.	Dir. Engg.	Up to Rs. 1.00 Lacs in each case	
		EE	Up to Rs. 0.25 Lacs in each case with annual limit of Rs. 1.00 Lacs	
8	To sanction purchase of spare parts in emergent cases, without inviting	EE	Up to Rs. 0.50 Lacs. (maximum annual limit-Rs. 2.00 Lacs)	

JAL

	tenders.			
9	To pass indents on other department articles required for sanctioned works.	EE	Full power	
10	To sanction the limits of Reserve stocks of divisions	JDC	Full power	
11	To sanction estimates for repair and carriage of tools and plants subject to specific A&F.	DE	Full power	
		SE	Up to Rs. 1.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 0.50 Lacs	
12	To accept bids for the sale of tools and plants declared surplus by the competent authority in accordance with rules.	JDC	Full power	As per procedure laid down in rule 16 to 27 of GF&AR vol I part II.
		DE	Up to Rs. 150.00 Lacs	
		SE	Up to Rs. 25.00 Lacs	
		EE	Up to Rs. 5.00 Lacs	
13	To issue stock or other materials to works at stock or market rates whichever is greater when their issue is not provided for in the contract.	EE	Full power subject to the condition that a report should be made to DE and DF stating the amount of the issue and the circumstances require it.	
14	To declare any stores (including tools & plants stocks and materials received from work dismantled) as surplus or unserviceable and sanction their sale by public auction or destruction.	DE	Full power	Note: - 3. These monetary limits refer to original purchase price which may be estimated if original price is not known. 4. Relevant provisions of GF&AR shall be <i>mutatis mutandis</i> adhered to.
		EE	Up to Rs. 0.50 Lacs.	
			Note: A report should be made to the Director (Finance). Detailed survey report shall be prepared and verified by committee.	
15	To sanction rate for hiring of departmental tool & plans	DE	Full power subject to rules	With prior concurrence from JDC
16	To sanction rate for hiring of departmental tool & plants and other materials obtained for external sources.	EE	Full power for each type of machine Rs. 10000/- only in emergent case after recording reasons.	With prior concurrence from JDC

17	To approve and counter sign indents for instruments mathematical instruments, office calculator etc.	DE	Full power	
		EE	Full power if within the scale sanctioned for the division.	
18	To sanction after due investigation the write off value of all type of stores, and plant lost destroyed or damaged by accident, negligence, and fraud or otherwise.	JDC	Full power	As per GF&AR Volume I part II Rule 20
		DE	Up to Rs. 3.00 Lacs in each case	
		SE	Up to Rs.1.00 lacs in each case	
		EE	Up to Rs.5,000/- each case	
19	To sanction the write off tool and plants which have become unserviceable after fair wear and tear.	DE	Full power	Subject to GF&AR Volume I part II Rule 17,18
20	To sanction after due investigation the write off of measurement books muster role which have been lost.	DE	Full Power	Note: 3. In each case while ordering write off the DE should pass a separate order after due Investigation & compliance of rules giving full details. Copy of the order should be endorsed to Director.(Finance) and JDC. 4. FIR must be done
21	To sanction estimates for losses on stock due to depreciation owing to a fall in prices or any cause or adjustment of losses on manufacturers accounts.	JDC	Full Power	
		DE	Up to Rs.0.50 lacs	
		SE	Up to Rs .20 lacs	
22	To write off discrepancies in accounts	EE	Up to Rs.50/-	
23	To Write off Infractionous expenditure on construction.	DE	1% of the contract value subject to a ceiling of Rs.50,000/- in consultation with Director(Fin.)	

24	To sanction compensation for the lands and crops standing on the land taken over by the authority for public works by negotiations provided amount is certified by land acquisition are reasonable and not excessive.	JDC	Full Power	
		DE	Rs. 5.00 lacs	
		EE	Up to Rs. 0.50 lacs. For each case.	
25	To sanction compensation, under the workmen's compensation Act of under any other law for the time being in force on as prescribed under the rules.	JDC	Full Power	Note: - If the award is pending for sanction before Competent authority. Director Engineering and SE may sanction an advance payment up to 75% of the compensation payable.
		DE	Up to Rs.2.00 lacs	
		SE	Up to Rs.1.00 lacs	
		EE	Up to Rs.0.50 lacs	

Note -

4. This Schedule of Powers shall come in to force from 1st day of May 2017 & amended on 18 May 2022 upon all work orders and agreements which are live and ongoing on that day.
5. Any matter not covered in this Schedule of Powers shall be exercised as per RTPP Act 2012&Rules 2013.
6. Any change in RTPP act-2012, Rule 2013, PWF&AR & GF&AR will supercede on this SOP

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से:-

बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

प्रस्ताव संख्या 11:- उपखण्ड कार्यालय, जोधपुर-दक्षिण एवं नवसृजित पंचायत कुडी भगतासनी के कार्यालय हेतु विवेक विहार योजना में 5000 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए।


प्रस्ताव संख्या 12:- घोडा घाटी सूरसागर सडक पर जो 'बोटल नेक' सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, में आने वाले निर्माण/अवरोध की भूमि के दस्तावेजों का विधिक परीक्षण करवाकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए व्यापक जनहित को देखते हुए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार हटाये जावे

तथा उक्त क्षेत्र का विकास किया जावे। इस हेतु यदि कोई नियमानुसार मुआवजा बनता है तो उक्त मुआवजे का हितबद्ध व्यक्ति को भुगतान किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2022/भाग-10 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 2.2./एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का क्रियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी। कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा)


(जय नारायण मीणा)
सचिव

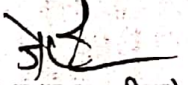
क्रमांक/बैठक/2022/भाग(10)/1176 to 1194

दिनांक :: २७-मई, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदय, नगर निगम, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर
- 5- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
- 6- संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 7- आयुक्त, नगर निगम-उत्तर/दक्षिण, जोधपुर
- 8- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 9- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
- 10- प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 11- उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर

- 12- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
- 13- निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 14- निदेशक- अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 15- उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 16- अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 17- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- 18- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 19-


(जय नारायण मीणा)
सचिव

श्री हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 18 मई, 2022 को सांय 4.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती कुंती परिहार देवडा, महापौर (उत्तर), नगर निगम, जोधपुर
2. श्री (डॉ) इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री डी.एल. आर्य, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री रामचन्द्र, अतिरिक्त कलक्टर-शहर, जोधपुर
5. श्री एम.एस. चारण, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
7. श्री राजेन्द्र सिंह भाटी, उप आवासन आयुक्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
8. श्री अरुण कमल शर्मा, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
9. श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
10. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता-शहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. श्री राकेश मेहता, अधिशाषी अभियन्ता-शहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
12. श्री जय नारायण, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर